



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931

No. 391]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 508(अ).—केंद्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में—

(1) नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“16-क (1) केन्द्रीय सरकार चीनी की उपलब्धता तथा ऐसे अन्य कारकों जिन्हें वह आवश्यक समझती है, और समिति से परामर्श के पश्चात्, चीनी के उत्पादन के लिए गन्ने की पेराई के साथ अपरिष्कृत चीनी के साथ-साथ प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपकरण की खरीद तथा संस्थापन के लिए चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने हेतु स्कीम को मंजूरी देगी और अधिसूचित करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात् :-

(i) विभिन्न प्रवर्गों के चीनी कारखानों को सवितरित की जाने वाली ऋण की राशि;

(ii) रीति और प्ररूप जिनमें इस नियम के अधीन आवेदन किए जा सकेंगे;

(iii) ऐसे ऋणों के सवितरण की रीति जिसमें अनुबंध या करार पर हस्ताक्षर करने की शर्त और ऋण के उपयोग की निगरानी सम्मिलित है;

(iv) अवधि, जिसके दौरान ऋण मंजूर करने की ऐसी स्कीम क्रियाशील होगी;

(v) अन्य कोई बात जो स्कीम में सम्मिलित किया जाना या अधिसूचित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) केवल ऐसे चीनी कारखाने, जिन्होंने सभी राशियों, जो चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के संबंध में देय हो गए हों, को पूर्ण रूप से लौटा दिया हो, उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित स्कीमों के अधीन ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(4) उप-नियम (1) के अधीन किसी भी स्कीम के अधीन मंजूर किए गए ऋणों तथा उसके साथ-साथ ब्याज की चुकौती चार समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी और ऋण के सवितरण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर आरम्भ होगी।”

3. नियम 17-क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“17-क(1) केन्द्रीय सरकार चीनी कारखानों द्वारा पेराई के लिए चीनी की उपलब्धता, देश में चीनी के उत्पादन की स्थिति

और ऐसे कारकों, जिन्हें वह आवश्यक समझती है, और समिति के साथ परामर्श के पश्चात् चीनी कारखानों को अपने विशिष्ट क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए ऋण देने हेतु स्कीम की मंजूरी और अधिसूचना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जारी करेगी, अर्थात् :-

- (क) बीजों की खरीद,
- (ख) उर्वरकों की खरीद,
- (ग) कीटनाशकों की खरीद ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित उपबंध किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) विभिन्न वर्गों के चीनी कारखानों को सवितरित की जाने वाली ऋण की राशि;
- (ii) रीति और प्ररूप जिसमें इस नियम के अधीन आवेदन किए जा सकेंगे ;
- (iii) ऐसी रीति जिनमें ऐसे ऋणों का सवितरण सविदा के हस्ताक्षर और ऋण के उपयोग की मानीटरिंग के बारे में शर्तसंमत किया जा सकेगा;
- (iv) अवधि जिसके दौरान ऋण मंजूर करने की ऐसी स्कीम क्रियाशील होगी ;
- (v) अन्य कोई बात जो स्कीम में सम्मिलित किया जाना या अधिसूचित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) केवल ऐसी चीनी कारखाने, जिन्होंने सभी राशियों, जो चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के संबंध में देय हो गए हों, को पूर्ण रूप से लौटा दिया हो, उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित स्कीमों के अधीन ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे ।

(4) उप-नियम (1) के अधीन किसी भी स्कीम के अधीन मंजूर किए गए ऋणों और उसके साथ ब्याज की चुकौती चार समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी और ऋण के सवितरण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर आरम्भ होगी ”।

4. नियम 25 में—

- (क) उप-नियम (1) में “चीनी विकास निधि नियम, 16, 17, 21, 22, और 23” शब्दों और अंकों के स्थान पर “चीनी विकास निधि नियम 16, 16-क, 17, 17-क, 21, 22 और 23 रखे जाएंगे;
- (ख) उप नियम (5) के उपबंधों में, “परन्तु यह कि” शब्दों के पश्चात् शब्दों और अंकों के स्थान पर “नियम 16-क और 17-क के अधीन लघु अवधि ऋण के बारे में, कोई चीनी कारखाना और” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

5. प्रारूप III-क का लोप किया जाएगा ।

[फा. संख्या 1-5/2009-एस.डी.एफ.]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 752(अ), तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और पश्चात्पूर्व संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे:—

- (i) सा.का.नि. 817(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 1984;
- (ii) सा.का.नि. 838(अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985;
- (iii) सा.का.नि. 551(अ), तारीख 6 मई, 1986;
- (iv) सा.का.नि. 235(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991;
- (v) सा.का.नि. 441(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992;
- (vi) सा.का.नि. 435(अ), तारीख 6 मई, 1994;
- (vii) सा.का.नि. 27(अ), तारीख 12 जनवरी, 1996;
- (viii) सा.का.नि. 656(अ), तारीख 21 नवम्बर, 1997;
- (ix) सा.का.नि. 91(अ), तारीख 12 फरवरी, 2001;
- (x) सा.का.नि. 886(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2001;
- (xi) सा.का.नि. 443(अ), तारीख 21 जून, 2002;
- (xii) सा.का.नि. 584(अ), तारीख 19 अगस्त, 2002;
- (xiii) सा.का.नि. 67(अ), तारीख 29 जनवरी, 2003;
- (xiv) सा.का.नि. 241(अ), तारीख 25 मार्च, 2003;
- (xv) सा.का.नि. 787(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2003;
- (xvi) सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2003;
- (xvii) सा.का.नि. 953(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2004;
- (xviii) सा.का.नि. 72(अ), तारीख 23 जनवरी, 2004;
- (xix) सा.का.नि. 687(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2004;
- (xx) सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2004;
- (xxi) सा.का.नि. 149(अ), तारीख 2 मार्च, 2005;
- (xxii) सा.का.नि. 451(अ), तारीख 4 जुलाई, 2005;
- (xxiii) सा.का.नि. 558(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006;
- (xxiv) सा.का.नि. 118(अ), तारीख 9 मार्च, 2007;
- (xxv) सा.का.नि. 697(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2007;
- (xxvi) सा.का.नि. 699(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2007;
- (xxvii) सा.का.नि. 738(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2007;
- (xxviii) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2007;

- (xxx) सा.का.नि. 115(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008;
 (xxx) सा.का.नि. 279(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2008;
 (xxxi) सा.का.नि. 388(अ), तारीख 19 मई, 2008.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2009

G.S.R. 508(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983,

(1) after rule 16, the following rule shall be inserted, namely,

“16- A (1) The Central Government, having regard to the availability of sugar and such other factors as it may consider necessary, and after consultation with the Committee, may sanction and notify schemes, to give loans for modernisation of sugar factories to purchase and install machinery and equipment required for simultaneous processing of raw sugar with crushing of cane for the manufacture of sugar.

(2) under sub-rule (1) the schemes may provide for the following, namely:

- (i) the amount of loan that may be disbursed to various categories of sugar factories;
- (ii) the manner and form in which applications may be made under this rule;
- (iii) the manner in which such loans may be disbursed including the condition regarding signing of contract or agreement and monitoring of utilisation of the loan;
- (iv) the period during which such scheme for grant of loans will be operative;
- (v) any other matter which is required to be made or notified in the scheme.

(3) Only such sugar factories as have fully repaid all sums, which have become due in respect of sugar development fund and levy sugar price equalization fund will be eligible to

apply for loan under the schemes notified under sub-rule (1).

(4) The repayment of loans sanctioned under any scheme under sub-rule (1) together with interest shall be made in four equal annual instalments and shall commence on expiry of one year from the date of disbursement of the loan.”

3. For rule 17-A, the following shall be substituted, namely,—

“17 - A (1) The Central Government, having regard to the availability of sugarcane for crushing by the sugar factories, situation of sugar production in the country and such other factors as it may consider necessary, and after consultation with the Committee, may sanction and notify schemes to give loans to sugar factories for the development of sugarcane in their specified areas for the following purposes, namely,

- (a) purchase of seeds,
- (b) purchase of fertilizers,
- (c) purchase of pesticides.

(2) under sub-rule (1) the schemes may provide for the following, namely,

- (i) the amount of loan that may be disbursed for various categories of sugar factories;
- (ii) the manner and form in which applications may be made under this rule;
- (iii) the manner in which such loans may be disbursed including the conditions regarding signing of contract and monitoring of utilisation of the loan;
- (iv) the period during which such scheme for grant of loans will be operative;
- (v) any other matter which is required to be made or notified in the scheme.

(3) Only such sugar factories as have fully repaid all sums, which have become due in respect of sugar development fund and levy sugar price equalization fund will be eligible to apply for loan under sub rule (1).

(4) The repayment of loans sanctioned under any scheme notified under sub-rule (1), together with interest shall be made in four equal annual instalments and shall commence on expiry of one year from the date of disbursement of the loan.”

4. In rule 25,

- (a) in sub-rule (1), for the words and figures “Sugar Development Fund Rules 16, 17, 21, 22 and 23”, the words and figures “Sugar Development Fund Rules 16, 16-A, 17, 17-A,

21, 22 and 23" shall be substituted;

- (b) in the proviso to sub-rule (5), after the words "provided that" the words and figures "in case of short term loans under rules 16-A and 17-A, any sugar factory and" shall be substituted.

5. "Form III-A" shall be omitted.

[F. N. 1-5/2009-SDF]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Footnote : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R 752(E), dated 28-9-1983 and were subsequently amended by the following notifications:

- | | |
|---|---|
| (i) G.S.R 817(E), dated the 20th December, 1984; | (xi) G.S.R 443(E), dated the 21st June, 2002; |
| (ii) G.S.R 838(E), dated the 14th November, 1985; | (xii) G.S.R 584(E), dated the 19th August, 2002; |
| (iii) G.S.R 551(E), dated the 6th May, 1986; | (xiii) G.S.R 67(E), dated the 29th January, 2003; |
| (iv) G.S.R 235(E), dated the 24th April, 1991; | (xiv) G.S.R 241(E), dated the 25th March, 2003; |
| (v) G.S.R 441(E), dated the 28th April, 1992; | (xv) G.S.R 787(E), dated the 6th October, 2003; |
| (vi) G.S.R 435(E), dated the 6th May, 1994; | (xvi) G.S.R 895(E), dated the 19th November, 2003; |
| (vii) G.S.R 27(E), dated the 12th January, 1996; | (xvii) G.S.R 953(E), dated the 17th December, 2004; |
| (viii) G.S.R 656(E), dated the 21st November, 1997; | (xviii) G.S.R 72(E), dated the 23rd January, 2004; |
| (ix) G.S.R 91(E), dated the 12th February, 2001; | (xix) G.S.R 687(E), dated the 21st October, 2004; |
| (x) G.S.R 886(E), dated the 6th December, 2001; | (xx) G.S.R 739(E), dated the 9th November, 2004; |
| | (xxi) G.S.R 149(E), dated the 2nd March, 2005; |
| | (xxii) G.S.R 451(E), dated the 4th July, 2005; |
| | (xxiii) G.S.R 558(E), dated the 15th September, 2006; |
| | (xxiv) G.S.R 118(E), dated the 9th March, 2007; |
| | (xxv) G.S.R. 697(E), dated the 7th November, 2007; |
| | (xxvi) G.S.R 699(E), dated the 8th November, 2007; |
| | (xxvii) G.S.R 738(E), dated the 29th November, 2007; |
| | (xxviii) G.S.R 749(E), dated the 5th December, 2007; |
| | (xxix) G.S.R. 115(E), dated the 28th February, 2008; |
| | (xxx) G.S.R. 279(E), dated the 10th April, 2008; |
| | (xxxi) G.S.R. 388(E), dated the 19th May, 2008. |